# लघु एवं कुटीर उद्योग – विश्लेषण

**डॉ. नीलम गोयल**
श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय,दिल्ली विश्वविद्यालय.

Received: July 03, 2018 Accepted: August 18, 2018

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग जिसे MSME के नाम से भी जाना जाता है। भारत में ही नहीं अपितु विश्व की बहुत सी विकसित एवं विकासशील देशो के आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं। MSME सेक्टर के इसी महत्वपूर्ण योगदान के कारण इसे भारतीय अर्थव्यव्स्था के विकास के इंजन के रूप में देखा जाता है। भारत जैसे बड़े देश में जहाँ प्रतिवर्ष एक करोड़ से अधिक नए लोग रोजगार पाने वालो की संख्या में जुड़ जाते हैं और सरकार इस बड़ी संख्या के लिए रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराने में असफल रहती हैं। ऐसे में MSME सेक्टर ही ऐसा सेक्टर है जो बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराता है और देश की बेरोजगारी को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत जैसे देश में MSME सेक्टर की महत्ता इस बात से समझनी चाहिए की कुल औद्योगिक इकाईयो में से लगभग 90% इकाईया MSME सेक्टर में आती है और भारत की लगभग 40% श्रमशक्ति को MSME सेक्टर ही रोजगार उपलब्ध कराता है। इस सेक्टर की एक बड़ी खूबी यह है की यह इतनी बड़ी संख्या में रोजगार तो उपलब्ध कराता है परन्तु वह भी कम पूंजी के निवेश पर । भारत जैसे देश में जहाँ पूँजी की उपलब्धता कम, महंगी तथा अनिश्चित है ऐसे देश में कम पूँजी के साथ अधिक रोज़गार उपलब्ध कराना, देश के संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए अति आवश्यक है। भारत जैसे बड़े देश में यह विकास की क्षेत्रीय असमानता तथा पूँजी व आय की असमानता को भी संतुलित करता है। MSME सेक्टर भारत की प्राचीन हस्तकलाओं, दस्तकारी, कारीगरी व प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को सहेजने जैसे महत्वपुर्ण कार्य को करता है। कश्मीर का कालीन उद्योग, बनारस का सिल्क व्यापार, फ़िरोज़ाबाद की चूड़ियां, कन्नौज का इत्र, लखनऊ की चिकनकारी आदि ऐसे अनेकों पुराने उद्योग हैं जो हमारी सांस्कृतिक विरासत के रूप में जाने जाते हैं। इनको सहेजने का कार्य MSME सेक्टर ही करता हैं। इन सबके अतिरिक्त बड़े उद्योगों की व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा कर सहयोगी इकाई का काम करता है जिससे देश की सामाजिक आर्थिक एवं समावेशी विकास में सहयोग प्रदान किया सके।

आज भारत में लगभग 8,000 से अधिक पारम्परिक व आधुनिक वस्तुओ का उत्पादन MSME सेक्टर में होता हैं। भारत सरकार के एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 5 खरब डॉलर होने की संभावना है और यह बिना MSME सेक्टर के महत्वपूर्ण भागीदारी के असंभव है। विकास, रोज़गार तथा बहुउद्देशीय लाभ की इन्ही क्षमताओ के कारण भरत सरकार विभिन्न नीतिगत उपायों से MSME सेक्टर को लगातार मजबूर करने की और प्रयासरत है।

साल 2015-16 में इस सेक्टर से जुड़े 633.88 लाख उद्यमों ने 11.10 करोड़ लोगों को रोजगार दिया और इनसे जुडी निर्यात की कीमत 8,492 बिलयन रूपये तक पहुंची। साल 2012-13 में 18100 बिलियन रूपये का आउटपुट दिया। (RBI 2017) 2014-15 में MSME की सकल घरेलू उत्पाद में 30.74 फीसदी की भागीदारी की। जिसमे से MSME के उत्पाद क्षेत्र की जीडीपी में भागेदारी 6.11 फीसदी थी इसमें से सेवा क्षेत्र की जीडीपी में भागीदारी 24.63 फीसदी थी। (MSME मंत्रालय 2017)

भारत सरकार सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम क्षेत्र की क्षमताओं व राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में इसकी महत्ता को पहचानती है। इसी लिए सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों की कठिनाईयों को दूर करने व विकास को नयी दिशा देने के हेतु निति निर्माण में सतत प्रयासरत हैं। वर्ष 2007 में इसी लिए सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के लिए अलग से मंत्रालय बनाया गया तथा MSME सेक्टर को प्रोहत्सान देने के लिए ऋण की उपलब्धता को बढ़ाने, तकनीकी गुणवत्ता में सुधार तथा प्रौद्योगिकी के लिए योजनाए तथा विपणन सुविधाओ का विकास आदि शामिल है। ऋण की उपलब्धता बढ़ाने हेतु (MSME) सेक्टर के लिए ऋण गारंटी न्यास का गठन किया तथा इसमें बिना कोलेटरल के ऋण प्राप्त करने की सीमा को एक करोड़ से बढ़ा कर दो करोड़ किया गया। प्रौद्योगिकी उन्ययन तथा कौशल विकास के लिए 18 प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना की हैं जो की प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध करने में सहायक होते है। इस दिशा में गुणवत्ता सुधार हेतु के वी.आई.सी., कायर बोर्ड, N.S.I.C. आदि को ISO मानकों को अपना कर प्रमाण पत्र हासिल किया तथा जेड जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट की शुरुआत की। इकाइयों व समूहों में क्षमता निर्माण तथा सशक्तिकरण के लिए क्लस्टर निति को सुदृढ़ बनाना। (MSME) सेक्टर में विपणन में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु सरकारी उपक्रमों को 3 वर्षो की अवधि के बाद कुल खरीद का 20 प्रतिशत अनिवार्य रूप से सूक्ष्म व लघु उद्योगों से खरीदना होगा। फ़रवरी 2017 में पेश बजट में 250 करोड़ से कम टर्नओवर वाला (MSME) के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 30 प्रतिशत से 25 प्रतिशत कर दिया गया है। स्टार्ट अप स्टैंड अप मुद्रा लोन आदि से छोटे-छोटे उद्योगों को स्थापित कर सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास किया हैं। सुविधाओं को बढ़ाने व सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों को बढ़ने के लिए MSME मंत्रालय व उसके संगठनों द्वारा नियोजित कार्यक्रम व योजना द्वारा निम्न सुविधाओं को सुनिश्चित करने का प्रयास जारी हैं।

1. वित्तीय संस्थानों / बैंको से ऋण का समुचित प्रवाह,
2. प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए सहयोग,
3. आधुनिक परीक्षण सुविधाएँ और गुणवत्ता प्रमाणन,

4. आधुनिक प्रबंधन प्रणालियों तक पहुँच,
5. प्रशिक्षण सुविधाओं के माध्यम से उद्यमिता विकास और कौशल उन्नयन,
6. उत्पाद के विकास डिजाईन और पैकजिंग के लिए सहयोग,
7. श्रमिकों का कल्याण,
8. घरेलु और निर्यात बाज़ारों में बेहतर पहुँच के लिए सहायता,
9. इकाइयों व उनके समूहों के क्षमता निर्माण,
10. सशक्तिकरण को प्रोहत्साहन देने के लिए क्लस्टरवार कदम उठाना।

यदि भारत वर्ष 2025 तक 5 ख़राब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है। तो बिना MSME सेक्टर की समुचित भागीदारी के यह संभव नहीं है तथा चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे पडोसी देशों से बढ़ती होड़ के कारण मजबूत रणनीति द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल विकास के द्वारा उत्पादन क्षमता में वृद्धि, लागत में कमी, नए गुणवत्ता पूर्ण उत्पाद तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन कर बिक्री को बढ़ाकर अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाना होगा यही समय की मांग व आवश्यकता हैं।

**सन्दर्भ**

1. सूक्ष्म, लघु व मध्यम मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2016-17।
2. मार्गन स्टेनलों का रिसर्च पेपर - नेक्स्ट इंडिया।
3. प्रेस सूचना ब्यूरो भारत सरकार और अन्य प्रेस विज्ञप्ति लेख ।
4. राष्टीय विनिर्माण नीति (एनएमपी) और सार्वजानिक खरीद नीति एम एस ई आदेश 2012।
5. भारत में एमएसएमईज़ की समस्याएं, रिसर्च गेट पब्लिकेशन, 10 मई 2016।
6. स्टेटस एंड इमर्जिंग नीड्स स्माल इंडस्ट्रीज डेवेलपमेंट बैंक ऑफ़ इंडिया, लखनऊ।
7. ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फॉर इंटरप्राईजेज इन अन ऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर-स्टेटस, कंस्ट्रेन्ट एंड रेकमेंडेशन्स ऑन टेक्नोलॉजी, भारत सरकार ।